

Starred Question No. 562 on the 17th December, 1964, regarding the affairs of Sriram Durga Prasad of Nagpur and state:

(a) the reasons for the inordinate delay in the completion of the investigation;

(b) when the proposed prosecution under the provisions of the Sea Customs Act, 1878 read with Foreign Exchange Regulations Act, 1947 will be launched;

(c) whether a special judge or tribunal will be appointed to try the persons concerned; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) When the searches were in progress, Shri Sriram Durga Prasad filed two writ petitions, one before the Nagpur Bench of Maharashtra High Court and the other before the Andhra Pradesh High Court at Hyderabad. On these petitions, stay orders were granted restraining the Department from scrutinising the documents, pending the hearing and disposal of the writ petitions. Proper investigations could start only after the vacation of these orders by the Nopur Bench in February 1964 and by the Andhra Pradesh High Court in November, 1964.

(b) The question of prosecution will be considered after the investigations are completed.

(c) and (d). The matter does not arise at this stage.

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय

13. { श्री मधु लियवे :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों तथा जिलों में सही सही प्रति व्यक्ति वार्षिक आय

2148 (Ai) LSD—3.

का पता लगाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है ताकि देश के सभी राज्यों तथा जिलों के समान विकास के लिए विकास योजनाएं बनाते समय उस पर विचार किया जा सके ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : आयोजन के लिए राज्य की आय के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से निवेदन किया है कि वह राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के सहयोग से सालाना आधार पर राज्य आय का, तुलनात्मक अनुमान तैयार करने का काम करे। मानक उद्देश्य और प्रणालियां निर्धारित कर दी गई हैं और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्य सांख्यिकी ब्यूरो को प्रशिक्षण सुविधायें तथा विशेष विषयों पर तकनीकी सलाह दी है। समस्या समान कार्यप्रणाली निश्चित करने की ही नहीं है अपितु राज्य स्तर पर कई वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित अर्थ-व्यवस्था के मूलभूत आंकड़ों में सुधार करने की है। आय के तुलनात्मक अनुमानों को तैयार करने का अल्पकालीन कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। इसका आधार आय के वे अनुमान हैं जो राज्य स्तर पर 1960-61 से 1962-63 तक के वस्तु उत्पादक केन्द्रों के बारे में योजना आयोग के उपयोग के लिए सब सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा तैयार किये गये हैं।

मुद्रणालय

14. { श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछबाय :
श्री श्रींकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चौथी योजना की अवधि में देश में पांच और मुद्रणालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उन को भी इस में भाग लेने दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) चौथी योजना में दो फोटो-लीथो और पांच फार्मस मुद्रणालय स्थापित करने का विचार है।

(ख) एक फोटोलीथो मुद्रणालय फरीदाबाद में स्थापित किया जायेगा और एक फार्मस मुद्रणालय गाज़ियाबाद में। बाकी के मुद्रणालयों के स्थान का अभी निश्चय नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

अमरीकी सहायता

15. { श्री श्रींकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सहायता के बारे में बातचीत करने के लिए भारत सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि-मंडल अमरीका जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी जायेगी और सहायता किस रूप में होगी;

(ग) क्या अन्य देशों को भी ऐसे प्रतिनिधि-मंडल भेजने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों को :

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)

(क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

जीवन बीमा निगम द्वारा विये जाने वाले ऋण

16. श्री श्रींकार लाल बेरवा :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अचल सम्पत्तियों को बन्धक के रूप में रख कर ऋण देने की योजना को हाल में दस और नगरों में लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो किस नारीख से तथा उन नगरों के क्या नाम हैं; और

(ग) योजना के निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :

(क) और (ख). पहली जनवरी, 1965 से यह योजना नीचे लिखे दस और नगरों में लागू की गयी है :—

आगरा अजमेर, आसन सोल,
जबलपुर, जालन्धर, लुधियाना, मेरठ,
नासक, राजकोट और वाराणसी।

(ग) योजना की वर्तमान शर्तों में, जो इस प्रकार हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है :—

(1) ब्याज की दर 8 प्रतिशत वार्षिक और भ्रदायगी हर छमाही। ब्याज और मूल की किस्तों की ठीक समय पर भ्रदायगी करने पर ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट;

(2) अधिकतम भ्रवधि 15 वर्ष;

(3) मूल की किस्तों की भ्रदायगी हर छमाही; और